**Sale of outdated Medicines**

2798. SHRI RAJNATH SINGH SURYA': Will the Minister of CHEMICAL AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a racket of selling outdated medicines in market by erasing old date and putting a new date;

(b) if so. what action has been or is being proposed to be taken in such cases;

(c) in how many such cases action has been taken during 1997-98; and

(d) what was the level of involvement i.e. drug manufacturers sellers or medical representatives?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) to (d) Information is being collected.

**Import of LNG**

2799. SHRI S.M. KRISHNA:
SHRI SURESH KALMADI:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have outlined LNG import strategy recently if so, the details thereof including the strategy hitherto being following;

(b) the details of liquified Natural Gas imported during last two years, year-wise and the countries from which the LNG was imported indicating the cost thereof in dollar as well rupees terms;

(c) whether a Committee under the Chairmanship of IFFCO M.D. was constituted to look into import of LNG for fertilizer sector if so, the details of the study conducted by the Committee; and;

(d) the action taken on the said report/ study?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) to (d) The LNG is placed in the OGL category but it has not so far been imported in India from any country. 100% Foreign Direct Investment is permitted in the manufacture of LNG in the country. The LNG importers can market the regasifled LNG to the consumers at market prices.

A Core Group on Liquified Natural Gas (LNG) was constituted on 31.7.98 under the chairmanship of the Managing Director (IFFCO) with a view to exploring the feasibility of importing LNG by forming a consortium of fertilizer companies alongwith other interested economic operators for fertilizer sectors such as power, domestic fuel etc. The core group submitted its report to the Govt, on 22.3.1999. The Core Group has recommended an integrated chain consisting of liquifaction plant located overseas with storage and dedicated port facilities, cryogenic LNG tankers for transportation of LNG, receiving terminal with storage tanks and regasification facilities and a delivery system of pipelines and compressors to supply regasified LNG to fertilizer and other consumers. The Core Group has proposed the implementation of the project in two phases with the capacity in each phase being 3.5 million tonne per annum at the estimated cost of Rupees 21,832 crores with phase-I and phase-II costs being Rs. 13,846 crores and Rs. 7.986 crores respectively.

As the report has been recently received, no tangible action could be taken so far.

**उर्वरकों के मूल्यों का निर्धारण**

2800. **श्री राजमोहिन्दर सिंह** :

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

क्या रसायन और उवर्रक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार द्वारा वर्ष 1998 में एक उच्च शक्ति प्रापत समिति का गठन किया गया था

जिसे उर्वरकों को मूल्यों के निर्धारण पर विचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच हैं कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अप्रैल, 1998 में सौप दी थी,

(ग) यदि हां, तो समिति की रिपोट्र संबंधी ब्यौरा क्या हैं और क्या सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट पर विचार करके उसे कार्यान्वित करने का भी निर्णय लिया हैं, और

(घ) यदि हां, तो अब तक किन-किन सुझावों को क्रियान्वित किया जा चुका हैं ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा0 ए0 के0 पटेल) :** (क) और (ख) यूरिया पर राजसहायता प्रदान करने की विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा करने तथा वैकल्पिक विस्तृत वैज्ञानिक एवं पारदर्शी प्रणाली का सुझाव देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति समीक्षा समिति (एच पी सी ) का गठन किया गया था । उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य निर्धारण समिति (एच पी सी ) ने अप्रैल, 1998 में अपनी रिपोट्र प्रस्तुत की ।

(ग) और (घ) उच्चाधिकार मूल्य निर्धारण समिति (एच पी सी) ने अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान यूरिया निर्माता एककों के लिए प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता योजना ( आर पी एस ) को बंद करने की सिफारिश की । इसने उसकी जगह नामेंटिव रेफरल मूल्य (आर पी एस ) व्यवस्था बनाने और राजसहायता को एन आर पी जमा डीलरों का लाभ और औसत भाड़ा और फार्मगेट मूल्य (एफ जी पी) के बीच के अंतर के बराबर समान रूप से निर्माताओं के माध्यम से दिए जाने की सिफारिश की । इसके अलावा इसने नेफथा, कोयला ईधन तेल तथा एलएसएचएस पर आधारित यूरिया संयत्र के संबंध में फीड स्टाक अवकुलन लागत पुनर्भुगतान (एफ डी सी आर) की सिफारिश की हैं । उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य निर्धारण समिति (एच पी सी) के विभिन्न सिफारिशों की जांच के दौरान यह महसूस किया गया हैं कि विद्यमान यूरिया एककों के लिए एक समान मूल्य से उद्योग के विषम संघटन के कारण गंभीर कठिनाईयां आएगी । इस प्रकार आर पी एस में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संशोधित प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता योजना को बनाना उपयुक्त समझा गया हैं । एम आर पी एस के संबंध में प्रस्ताव और नए उर्वरक एककों के लिए मूल्य नीति के संबंधी में उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य निर्धारण समिति (एच पी सी) की सिफारिशों के लिए उर्वरक उद्योग समन्वय समिति को भेज दिया गया हैं । उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ आई सी सी ) की सिफारिशें प्राप्त होने पर एम आर पी एस और एच पी सी की अन्य सिफारिशों के संबंध में प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा ।

**Toxic substances in the Held of agriculture**

2801. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 70,000 toxic substances exist in the field of Agriculture by way of poisonous pesticides;

(b) if so, whether Government have taken any action to initiate an enquiry in the availability of these substances in the market;

(c) which are the sources (Indian & Western) from which the poisonous pesticides are being imported or procured; and

(d) what steps Government have taken to provide treatment and analytical support for poison cases besides providing information on the toxic compounds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) While a large number of pesticides are used world over, in India only 144 pesticides which are safe for human beings, animals and the environment have been registered for use in agriculture, by the Registration Committee constituted under the Insecticides Act, 1968.

(c) About 100 foreign sources (including western countries) have been approved by the Registration Committee for import of pesticides. In India there are more than 125 producers of technical grade pesticides.

(d) Pesticides are toxic in nature and can cause poisoning if mis-used/abuscd. The various steps taken by the